



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42547 वर्ष 2025

शाहरुख

आवेदक/आवेदकों

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता: कुशाग्र श्रीवास्तव, शाहरुख

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत यह वर्तमान जमानत याचिका आवेदक शाहरुख की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें विचारण के लंबित रहने के दौरान, पुलिस थाना बिसरख, जिला गौतम बुद्ध नगर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 380/2025, अंतर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और असमाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी गुप्त इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अनुलग्नक संख्या 3 में संलग्न गिरोह-वृत्तचित्र में दो आपराधिक मामले दर्शाए गए हैं और दोनों मामलों में आवेदक जमानत पर है। गिरोह-वृत्तचित्र में दर्शाए गए मामलों के अलावा, आवेदक का एक आपराधिक इतिहास भी है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में न तो सहायता की है और न ही उसका समर्थन किया है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 28.07.2025 से जेल में बंद है, वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मामलों के अलावा आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य मामला नहीं बताया है।

सभी तथ्यों, प्रकृति और अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, यह जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

आवेदक को उपरोक्त उल्लिखित मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, समान राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।



(iii) आवेदक को मुकदमे की शुरुआत, आरोप निर्धारण और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालयके समक्ष उपस्थित रहना होगा।

(iv) आवेदक को यह वचन देना होगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा, जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहना होगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य से ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले की योग्यता पर राय के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

14 जनवरी, 2026

मिनी